Vidhan Sabha Business

No. Rev.B .A(3)3/2021 Loose
Government of Himachal Pradesh
Revenue Department

To

The Secretary,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha
Shimla-171004

Dated Shimla-2, the 11th March, 2022

Subject: The Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Bill, 2022.

Sir,

I have honour to give notice of my intention to introduce the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Bill, 2022 in the present Session of H.P. Vidhan Sabha. It is also requested that time period for introducing the above Bill in H.P. Vidhan Sabha may kindly be exempted.

Three authenticated alongwith 80 copies of the aforesaid Bill are sent herewith for taking further necessary action.

Yours faithfully,

(Mahender Singh Thakur)
Revenue Minister, H.P.

Endst. No. As above Dated Shimla-2, Shimla-2, the 11th March, 2022

Copy is forwarded to the following for information and necessary action:

1. The Principal Secretary-cum-LR (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Revenue Minister, H.P. Shimla-2.

Principal Secretary (Revenue) to the
Government of Himachal Pradesh

***

2022 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 17 का प्रतिस्थापन।

2022 का विधेयक संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:––

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 2022 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–– धारा 17 का प्रतिस्थापन।

"**17. राजस्व अधिकारियों की कार्यवाहियों को मंगवाने, परीक्षण करने और पुनरीक्षण करने की शक्ति.**––वित्तायुक्त अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी के पास लंबित या उसके द्वारा निपटाए गए अथवा उसके समक्ष संस्थित किसी मामले का अभिलेख किसी भी समय मंगवा सकेगा और ऐसा आदेश, पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु वह इस धारा के अधीन, किसी अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की किसी कार्रवाही या आदेश को उलटने का या उपांतरित करने तथा प्राइवेट व्यक्तियों के मध्य अधिकार के किसी प्रश्न पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, पारित नहीं करेगा।"।

अधिप्रमाणित

Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 17 की उप धारा (2) और (3) के विद्यमान उपबंध कलक्टरों और आयुक्तों को उनके नियंत्रणाधीन किसी राजस्व अधिकारी के पास लंबित या निपटाए गए किसी मामले के अभिलेख की मांग करने हेतु सशक्त करते हैं। किन्तु यदि किसी मामले में आयुक्त या कलक्टर की यह राय है कि की गई कार्यवाही या किया गया आदेश उपांतरित या पुनरीक्षित किया जाना चाहिए तो उसे मामले को अपनी सिफारिशों सहित आगामी आदेशों के लिए वित्तायुक्त को निर्दिष्ट करना होगा। पूर्वोक्त धारा के अधीन मामले पर विचार करते हुए आयुक्त या कलक्टर को समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, वित्तायुक्त पक्षकारों को ऐसी सिफारिशों पर आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु भी आबद्धकर है। इस प्रकार इस धारा के अधीन कार्यवाहियों की द्वैधता (डयूप्लिसिटि) है, जिसके परिणामस्वरूप पुनरीक्षण मामलों में अनावश्यक देरी और विलम्ब होता है। अतः पुनरीक्षण याचिका के माध्यम (चैनल) को संक्षिप्त (कम) करने के लिए, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के अधीन पुनरीक्षण की शक्तियों को केवल वित्तायुक्त के पास ही रखना समुचित है। इस प्रकार, वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अधिनियम में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ...., 2022

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व (संशोधन) विधेयक, 2022

हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(महेन्द्र सिंह ठाकुर)
प्रभारी मन्त्री।

अधिप्रमाणित

(राजीव भारद्वाज)
प्रधान सचिव (विधि)।

Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

शिमला :

तारीख : ...., 2022

इस संशोधन विधेयक द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) के उपबन्धों के उद्धरण

धारा :

17. **माल अधिकारी की कार्यवाही की पुनरावृत्ति तथा परीक्षा करने की शक्ति.**—(1) फाईनैन्शियल कमिश्नर अपने अधीन किसी माल अधिकारी के विचाराधीन या उसके द्वारा निर्णित किसी मुकद्दमें के कागजात मंगवा सकेगा।

(2) कमिश्नर अथवा कलक्टर अपने नियन्त्रणाधीन किसी माल अधिकारी के विचाराधीन या उसके द्वारा निर्णित किसी मुकद्दमें के कागजात मंगवा सकेगा।

(3) यदि किसी मामले (मुकद्दमें) में, जिसमें कमिश्नर या कलक्टर ने अभिलेख मंगाया है, की यह राय है कि उसमें की गई कार्यवाहियों को या किए गए आदेश को उपांतरित या उलट दिया जाना चाहिए, तो वह उस पर अपनी राय सहित मामले को फाईनैन्शियल कमिश्नर के पास उसके द्वारा आदेश के लिए भेज देगा।

(4) फाईनैन्शियल कमिश्नर किसी भी मामले में, जिसे उप–धारा (1) के अधीन मंगवाया हो या जो उसे उप–धारा (3) के अधीन भेजा गया हो, ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु वह अधीनस्थ राजस्व अधिकारी की किसी भी कार्यवाही को उलटने या उपांतरित करने वाला तथा प्राइवेट व्यक्तियों के मध्य अधिकार के प्रश्न पर प्रभाव डालने वाला कोई आदेश, उन व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना, इस धारा के अधीन पारित नहीं करेगा।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 3 OF 2022

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2022

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Substitution of section 17.

Bill No. 3 of 2022

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2022

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2022.

Substitution of section 17.

2. For section 17 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954, the following shall be substituted, namely:—

"17. ***Power to call for, examine and revise proceedings of Revenue Officers.***—The Financial Commissioner may at any time call for the record of any case pending before or disposed of by any Revenue Officer subordinate to him or instituted before him and may pass such order as he thinks fit:

Provided that he shall not, under this section, pass an order reversing or modifying any proceeding or order of a subordinate Revenue Officer and effecting any question of right between private persons without giving those persons an opportunity of being heard.".

Authenticated

Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The existing provisions of sub-sections (2) and (3) of section 17 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 empowers the Collectors and the Commissioners, to call for record of any case pending before or disposed of by a revenue officer under their control. But if in any case the Commissioner or the Collector is of the opinion that the proceeding taken or the order made should be modified or revised, he has to refer the matter with his recommendations to the Financial Commissioner for taking further orders. While considering the case under the aforesaid section, the Commissioner or the Collector has to provide opportunity of being heard to all the interested parties. Further, the Financial Commissioner is also bound to provide opportunity of being heard to the parties before passing an order on such recommendations. As such, there is duplicity of proceedings under this section, which results in un-necessary delay and pendency of the revision cases. Thus, in order to cut short the channel of revision petition, it is appropriate to keep the powers of revision under section 17 of the Act *ibid.* with the Financial Commissioner only. Hence, suitable amendments have been proposed in the Act for achieving the desired objectives.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(MAHENDER SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

Authenticated

Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

SHIMLA :

The , 2022.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954).

(MAHENDER SINGH THAKUR)
Minister-in-Charge.

(RAJEEV BHARDWAJ)
Pr. Secretary (Law).

Authenticated

SHIMLA :

The , 2022.

Jal Shakti/Hort./Rev./SWD Minister
Himachal Pradesh

EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE HIMACHAL PRADESH LAND REVENUE ACT, 1954 (ACT NO. 6 OF 1954) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL

Section :

17. Power to call for, examine and revise proceedings of Revenue Officers.—(1) The Financial Commissioner may at any time call for the record of any case pending before or disposed of by any Revenue Officer subordinate to him.

(2) A Commissioner or Collector may call for the record of any case pending before, or disposed of by, any Revenue Officer under his control.

(3) If in any case in which a Commissioner or Collector, has called for a record, is of the opinion that the proceedings taken or order made should be modified or reversed, he shall report the case with his opinion thereon for the orders of the Financial Commissioner.

(4) The Financial Commissioner may in any case called for by himself under sub-section (1) or reported to him under sub-section (3) pass such order as he thinks fit :

Provided that he shall not under this section pass an order reversing or modifying any proceeding or order of a subordinate Revenue Officer and effecting any question of right between private persons without giving those persons an opportunity of being heard.